

**राजेश पटेल
बनाम
झारखण्ड राज्य
(अपराधिक अपील संख्या 1149 / 2008)
15 मार्च 2013
[चंद्रमौलि के.आर. प्रसाद और
वी. गोपाल गौड़ा, न्यायाधीशगण]**

दंड संहिता, 1860:

धारा 376 - निचली अदालतों द्वारा दोषसिद्धि - माना गया: इस मामले में, अभियोक्ता द्वारा सुनाई गई अभियोजन की कहानी सबसे अधिक असंभाव्य और अप्राकृतिक है - जिस गवाह के बारे में कहा गया है कि उसने अभियोक्ता को घटनास्थल से बचाया था और अभियोक्ता के नियोक्ता ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया - जिस डॉक्टर ने अभियोक्ता की चिकित्सकीय जांच की थी और जांच अधिकारी की जांच नहीं की गई - निचली अदालतों ने यह मानते हुए गलती की कि उनकी गैर-परीक्षा ने बचाव पक्ष को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया - इसके अलावा, 11 दिनों की अत्यधिक देरी से मुकदमा चलाने के मामले में नुकसान हुआ - अभियोक्ता की गवाही सबसे अधिक अप्राकृतिक और विश्वास करने के लिए असंभव है और इसलिए, यह दोषसिद्धि और सजा को बनाए रखने के लिए इसे स्वीकार करने के लिए विश्वास को प्रेरित नहीं करती है - अभियोजन पक्ष के मामले ने उचित संदेह पैदा किया है - इसलिए, संदेह का लाभ अपीलकर्ता को मिलना चाहिए - विवादित निर्णय को रद्द किया जाता है - भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 136.

अपीलकर्ता पर अपनी परिचित और सहपाठी, जो नर्स के रूप में काम कर रही थी, के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया गया था। ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को धारा 376 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया और उसे 7 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने,

निर्णय: 1.1 अभियोक्ता द्वारा बताई गई अभियोजन की कहानी सबसे अधिक असंभाव्य और अस्वाभाविक है। अभियोक्ता आरोप को साबित करने वाली एकमात्र गवाह है। उसकी मां पीडब्लू 2 द्वारा उसके बयान की पुष्टि की मांग की गई है, जिसने अभियोक्ता द्वारा कथित अपराध के बारे में बताए गए कथन के आधार पर अभियोजन के मामले का समर्थन किया है। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि अपीलकर्ता और अभियोक्ता दोनों सहपाठी थे और पुस्तकों का आदान-प्रदान करने के कारण एक-दूसरे से अच्छे परिचित थे। अभियोक्ता ने कहा कि 14.2.1993 को, वह अपनी पुस्तक लेने के लिए अपीलकर्ता के घर गई और जब वह घर में दाखिल हुई तो उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और उसके साथ बलात्कार किया और उसे चाकू से धमकाया; कि अपीलकर्ता ने फिर उसे घर में बंद कर दिया और चला गया; कि लगभग आधे घंटे के बाद, दोनों

के एक सामान्य मित्र पीडब्लू 3 ने कमरे का ताला खोला। इस अवधि के दौरान उसने पड़ोसियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए शोर नहीं मचाया। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अभियोक्ता की गवाही अत्यंत अस्वाभाविक और विश्वास करने योग्य नहीं है और यह विश्वास पैदा नहीं करती है। [पैरा 8] [418-एच; 419-बी-एफ]

1.2 इसके अलावा, एफआईआर दर्ज करने में लगभग 11 दिनों की अत्यधिक देरी हुई है। अभियोक्ता द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण यह है कि वह अपने घर गई और अपनी माँ को घटना के बारे में बताया, और पीडब्लू 3 के आश्वासन पर कि वह मामले में कार्रवाई करेगा, उसकी माँ 2-4 दिनों तक चुप रही। एफआईआर दर्ज करने में 11 दिनों की अत्यधिक देरी अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है। असंतोषजनक कारण बताकर एफआईआर दर्ज करने में देरी को स्वीकार करने में निचली अदालतों द्वारा किए गए निष्कर्ष और अवलोकन इस न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किए जा सकते क्योंकि निष्कर्ष और कारण कानून की दृष्टि से गलत हैं। [पैरा 9] [420-बी-सी; 421-बी-सी]

1.3 इसके अलावा, अभियोजन पक्ष के गवाह 3, जो अपीलकर्ता और अभियोक्ता का साझा मित्र है और जिसने उसे घटनास्थल से बचाया था, ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसे मामले के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इस प्रकार, उसने अभियोजन पक्ष के कथन का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन पक्ष के गवाह 4 ने अपने साक्ष्य में कहा है कि अभियोक्ता उसके कक्ष में निजी तौर पर नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त कर रही थी। उसे शत्रुतापूर्ण माना गया है और अभियोजन पक्ष द्वारा उससे जिरह की गई। अपनी जिरह में उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने पुलिस को बताया था कि उसे घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसने आगे कहा है कि न तो अभियोक्ता और न ही उसकी माँ ने उसे घटना के बारे में बताया। अभियोजन पक्ष के गवाह 3 और अभियोजन पक्ष के गवाह 4 के साक्ष्य ने अभियोजन पक्ष के मामले को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। [पैरा 10 और 12] [421-डी-ई, एफ-जी; 422-एफ]

1.4 इसके अलावा, न तो डॉक्टर, जिसके बारे में कहा गया है कि उसने अभियोक्ता की मेडिकल जांच की है, और न ही आई.ओ. की अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करने के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष जांच की गई है। अपीलकर्ता ने ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ उच्च न्यायालय के ध्यान में यह बात लाने में सही किया कि उक्त दो महत्वपूर्ण गवाहों की जांच न किए जाने से उसके मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसलिए, ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष और कारण कि डॉक्टर और आई.ओ. की जांच न किए जाने से अपीलकर्ता के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है, पूरी तरह से गलत दृष्टिकोण है। इस कारण से भी, आरोपित निर्णय में दर्ज किए गए निष्कर्ष और कारण कि ट्रायल कोर्ट का यह मानना उचित था कि अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप साबित कर दिया है और उसने अभियोक्ता पर अपराध किया है, पूरी तरह से गलत है और यह कानून में पूरी तरह से असंतुलित है। [पैरा 11-12] [421-एच; 422-ए; 423-सी-ई]

1.5 निचली अदालतें, किसी भी तरह से, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर यह नहीं मान सकती थीं कि अपीलकर्ता धारा 376, आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध करने का दोषी है। अभियोजन पक्ष का मामला न तो स्वाभाविक है, न ही सुसंगत है और

न ही अपीलकर्ता की सजा और सजा को बनाए रखने के लिए संभावित है। इसलिए, संदेह का लाभ अपीलकर्ता को मिलना चाहिए। इस न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए विवादित निर्णय में हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता है, और तदनुसार इसे रद्द किया जाता है। [पैरा 12, 15 और 16] [422-एफ-जी; 425-डी-एफ-जी]

राजू बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2008) 5 एससीसी 133 - संदर्भित

राम कुमार बनाम हरियाणा राज्य (2006) 9 एससीसी 589 - उद्धृत।

केस लॉ संदर्भ:

(2006) 9 एससीसी 589 पैरा 5 का हवाला दिया गया

(2008) 5 एससीसी 133 पैरा 14 का हवाला दिया गया

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1149 वर्ष 2008

आपराधिक अपील संख्या 58/1999 में झारखंड उच्च न्यायालय के दिनांक 14.11.2006 के निर्णय एवं आदेश से।

अपीलकर्ता की ओर से संजय हेगड़े, शंकर एन., अरिजीत मजूमदार (एन. अन्नपूरानी के लिए)।

प्रतिवादी की ओर से अनिल कुमार झा, एस.के. दिवाकर।

न्यायालय का निर्णय किसके द्वारा सुनाया गया,

वी. गोपाल गौड़ा, जे. 1. यह आपराधिक अपील झारखंड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा आपराधिक अपील संख्या 58/1999 दिनांक 14.11.2006 में पारित निर्णय के विरुद्ध निर्देशित है, जिसमें उसने प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जमशेदपुर द्वारा एस.टी. संख्या 168/1994/172/1995 में पारित निर्णय और आदेश की पुष्टि की है। उक्त निर्णय द्वारा, अपीलकर्ता को धारा 376, आई.पी.सी. के तहत दोषी ठहराया गया और उसे सात वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

2. इस अपील में प्रस्तुत प्रतिद्वन्द्वी कानूनी तर्कों को समझने के उद्देश्य से अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में नीचे दिया गया है।

3. इस मामले में अभियोक्ता ने घाटशिला थाने में पुलिस के समक्ष बयान दिया है कि उसने दिनांक 14.2.1993 को पूर्वाह्न 11 बजे अपीलकर्ता के घर में घटी घटना का विवरण दिया है। उसने बताया कि वह पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला के मऊभंडार स्थित डॉ. प्रबीर भगत के नर्सिंग होम में नर्स के रूप में काम कर रही थी। अपीलकर्ता राजेश का घर, जो अभियोक्ता का सहपाठी लगता है, उस नर्सिंग होम के पास स्थित है, जिसमें अभियोक्ता नर्स के रूप में काम कर रही थी। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अपीलकर्ता के अनुरोध पर वह उससे अपनी किताब वापस लेने के लिए उसके घर गई थी। जैसे ही वह अपीलकर्ता के घर में दाखिल हुई, उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उस समय अपीलकर्ता के परिवार के सदस्य घर के अंदर मौजूद नहीं थे। जब अभियोक्ता ने शोर मचाने की कोशिश की तो अपीलकर्ता ने उसे डरा दिया और धमकी दी कि अगर उसने शोर मचाया तो उसे चाकू से मार दिया जाएगा। इसके बाद अपीलकर्ता ने उसके साथ बलात्कार किया। जब उसे अपने निजी अंग में दर्द महसूस हुआ तो वह चिल्लाना चाहती थी लेकिन अपीलकर्ता ने उसे चाकू दिखाकर चुप करा दिया।

बलात्कार का अपराध करने के बाद अपीलकर्ता घर से निकल गया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। आधे घंटे के बाद, चुनडीह के पूर्णेंदु बाबू ने आकर घर का ताला खोला और अभियोक्ता चुपचाप अपने घर लौट गई। अभियोजन पक्ष का यह भी मामला है कि वह अपने घर गई और अपनी मां को घटना के बारे में बताया। हालांकि, अभियोक्ता की मां श्री पूर्णेंदु बाबू के इस आश्वासन पर दो-चार दिनों तक चुप रही कि वह मामले में कार्रवाई करेंगे। इसके अतिरिक्त, यह आरोप लगाया गया कि अपराध करने के समय अपीलकर्ता ने अभियोक्ता को यह भी धमकी दी थी कि अगर उसने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई तो उसे मार दिया जाएगा।

4. निचली अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और उसे सात साल की कैद की सजा सुनाई। झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष विभिन्न कानूनी दलीलों का हवाला देते हुए आपराधिक अपील संख्या 58/1999 दायर करके इसकी सत्यता को चुनौती दी गई। अपीलकर्ता की ओर से कानूनी दलीलों पर विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय ने आरोपी की दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की और अपील को खारिज कर दिया। इस अपील में इसकी सत्यता को निम्नलिखित कानूनी दलीलों का हवाला देते हुए चुनौती दी गई है: कि निचली अदालतें यह समझने में विफल रही हैं कि अभियोक्ता की एकमात्र गवाही का इस्तेमाल अपीलकर्ता के खिलाफ उसे धारा 376, आईपीसी के तहत अपराध का दोषी ठहराने के लिए नहीं किया जा सकता था; कि अभियोजन पक्ष ने अभियोक्ता की मेडिकल जांच करने वाले डॉक्टर या जांच अधिकारी से पूछताछ नहीं की। इसलिए, अपीलकर्ता को अपराध का दोषी मानने वाला तथ्य कानूनी रूप से गलत है और इसे खारिज किया जाना चाहिए। अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री संजय हेगड़े द्वारा दिया गया एक और आधार यह है कि निचली अदालतें यह समझने में विफल रही कि अपीलकर्ता के घर में अभियोक्ता को बंधक बनाए जाने की कहानी को बनाए नहीं रखा जा सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि अपीलकर्ता और अभियोक्ता के एक सामान्य मित्र पीडब्लू 3 पूर्णेंदु बाबू, जिन पर अभियोक्ता को बंधक बनाए जाने से बचाने का आरोप है, ने इसका समर्थन नहीं किया, जिससे अभियोजन पक्ष की कहानी की घटनाओं की श्रृंखला टूट गई। इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि निचली अदालतें एफआईआर दर्ज करने में देरी को नोटिस करने में विफल रही, जिसे पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है। निचली अदालतों ने पीडब्लू 3 और पीडब्लू 4, अर्थात् पूर्णेंदु बाबू और नर्सिंग होम के डॉक्टर, जिसमें अभियोक्ता काम कर रही थी, के हस्तक्षेप के आधार पर एफआईआर दर्ज करने में देरी की व्याख्या की है, क्योंकि उन्होंने पीड़ित को पक्षों के बीच मामले को सुलझाने का आश्वासन दिया था। हालांकि, इन दोनों गवाहों को अभियोजन पक्ष द्वारा या तो पेश किया गया या मुकदमे के दौरान पक्षद्रोही घोषित किया गया। इसके अलावा, अपीलकर्ता ने तर्क दिया है कि निचली अदालतें अभियोक्ता और उसकी मां के बयान में गंभीर विरोधाभास पर विचार करने में विफल रही। अभियोक्ता ने अपने जिरह में कहा है कि डॉ. प्रवीर भगत-पीडब्लू 4 शाम को अपने चैंबर में थे, जब अपीलकर्ता पूर्णेंदु बाबू-पीडब्लू 3 के साथ नर्सिंग होम गई थी, जबकि अभियोक्ता की मां ने अपनी गवाही में कहा है कि घटना की तारीख को डॉ. प्रवीर भगत को घटना की सूचना नहीं दी जा सकी, क्योंकि डॉक्टर टाटा में थे। अपीलकर्ता के अनुसार, निचली अदालतों ने अभियोक्ता के बयान में विरोधाभास को

नजरअंदाज कर दिया है। एक तरफ वह कहती है कि वह 21.2.93 तक अपीलकर्ता से कभी नहीं मिली, दूसरी तरफ उसने कहा है कि कथित घटना की शाम को वह डॉ. प्रवीर भगत के डिस्पेंसरी में अपीलकर्ता से मिली थी। अपीलकर्ता ने अभियोजन पक्ष के स्पष्टीकरण के बारे में आगे तर्क दिया कि जब घर बंद था और उस पर अपराध किया जा रहा था, तो वह अलार्म नहीं बजा सकती थी, क्योंकि अपीलकर्ता ने उसे चाकू से धमकाया था, उसके बयान पर विश्वास करना असंभव है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह तब अलार्म बजा सकती थी, जब अपीलकर्ता ने कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार करने के बाद आधे घंटे के लिए अभियोक्ता को घर के अंदर बंद कर दिया था। उपर्युक्त सभी आधारों के लिए, अपीलकर्ता के वकील का तर्क है कि अपीलकर्ता पर लगाई गई सजा और सजा को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

5. वैकल्पिक रूप से, विद्वान वकील का तर्क है कि यदि अपीलकर्ता और अभियोजन पक्ष के बीच शारीरिक संबंध स्थापित होता है, तो यह सहमति से यौन संबंध का मामला था। वे दोनों इस तरह के संबंध में प्रवेश करने के लिए वयस्क थे और वे सहपाठी थे और एक-दूसरे से परिचित थे और कथित अपराध की घटना से पहले एक-दूसरे से मिलने-जुलने के लिए भी जाते थे। इसलिए, अपीलकर्ता ने कथित रूप से अपराध नहीं किया है। सजा के मुद्दे पर, विद्वान वकील ने राम कुमार बनाम हरियाणा राज्य के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है, क्योंकि वर्तमान मामले में अपीलकर्ता पहले ही 1 वर्ष और 8 महीने से अधिक कारावास की सजा काट चुका है और अपराध की तारीख से 20 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है और इसलिए उचित आदेश पारित करके अपील की अनुमति दी जा सकती है। अभियोक्ता और अपीलकर्ता दोनों विवाहित हैं और जीवन में बसे हुए हैं और इसके अलावा अपीलकर्ता कम उम्र का है। इसलिए, यह न्यायालय धारा 376, आईपीसी के प्रावधान के तहत दिए गए विशेष और पर्याप्त कारणों को दर्ज करके अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और लगाई गई सजा को अपीलकर्ता द्वारा न्यायिक हिरासत में पहले से ही बिताई गई अवधि तक कम किया जा सकता है और इसे कारावास के रूप में माना जा सकता है और उसे इस सीमा तक राहत दी जा सकती है जैसा कि **राम कुमार मामले (पूर्व में उल्लेखित)** में देखा गया था, यदि अपीलकर्ता की ओर से दिया गया मामला स्वीकार्य नहीं है।

6. दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के खिलाफ आरोप पर उच्च न्यायालय और निचली अदालत द्वारा दर्ज तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों को उचित ठहराने की मांग की। अभियोजन पक्ष के विद्वान वकील का तर्क है कि निचली अदालतों ने अभियोक्ता और उसकी मां की गवाही को स्वीकार करते हुए अभियुक्त को सही रूप से दोषी ठहराया है और उसे सात साल के कारावास की सजा सुनाई है और इस अपील में इस न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि अपीलकर्ता के वकील द्वारा ऊपर संदर्भित निर्णय वर्तमान मामले की तथ्यात्मक स्थिति के लिए अनुपयुक्त है और इसलिए, सजा में कमी करने के लिए इस अदालत की विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है और इस अपील को खारिज करने की प्रार्थना की।

7. पक्षों की ओर से प्रस्तुत किए गए उपरोक्त प्रतिद्वंद्वी कानूनी विवादों के संदर्भ में, हमने यह पता लगाने के लिए मामले की सावधानीपूर्वक जांच की है कि क्या आरोपित निर्णय इस आधार पर इस न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग करता है कि धारा 376, आईपीसी के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप पर उच्च न्यायालय द्वारा तथ्यों का समवर्ती निष्कर्ष और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर अपीलकर्ता के खिलाफ इस आरोप पर दर्ज किया गया निष्कर्ष कानून में गलत है और यदि ऐसा है, तो क्या इस न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में हस्तक्षेप की आवश्यकता है। निम्नलिखित कारणों को बताकर उक्त बिंदुओं का उत्तर अपीलकर्ता के पक्ष में दिया जाता है:

8. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अपीलकर्ता ने 14.2.1993 को अभियोक्ता पर बलात्कार का अपराध किया है। वह आरोप साबित करने वाली एकमात्र गवाह है। उसकी मां पीडब्लू 2 द्वारा भी इसकी पुष्टि की जानी है, जिन्होंने अभियोक्ता द्वारा कथित अपराध के वर्णन के आधार पर अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि अपीलकर्ता और अभियोक्ता दोनों सहपाठी हैं और पुस्तकों का आदान-प्रदान करने के कारण एक-दूसरे से अच्छे परिचित थे। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि उसने अपनी पुस्तक अपीलकर्ता को दी थी। उसने उसे पुस्तक वापस करने के लिए कहा और उसने उसे 14.2.93 को पुस्तक वापस लेने के लिए अपने घर जाने के लिए कहा। तदनुसार, वह अपीलकर्ता के घर गई। जब वह घर में दाखिल हुई तो उसने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उस समय उसने कोई शोर नहीं मचाया, सिवाय इसके कि उसने घर का दरवाजा बंद न करने पर ज़ोर दिया क्योंकि उस समय घर में कोई और नहीं था। अभियोक्ता का कहना है कि वह शोर नहीं मचा सकती थी क्योंकि अपीलकर्ता ने उसे चाकू दिखाकर धमकाया था। अभियोक्ता का आगे का मामला यह है कि उसने उसके साथ बलात्कार किया था। इसके अलावा उसने कहा है कि जब अपीलकर्ता उसके साथ बलात्कार कर रहा था तो उसे अपने गुप्तांग में दर्द हुआ और उस समय भी वह शोर मचाना चाहती थी, लेकिन उसने उसे शोर न मचाने के लिए चाकू दिखाया। इस प्रकार, अभियोक्ता द्वारा सुनाई गई अभियोजन की कहानी सबसे अधिक असंभव और अप्राकृतिक है। अपीलकर्ता के इस तर्क को उसकी ओर से दिए गए तर्क से और भी बल मिलता है कि अपराध करने के बाद अपीलकर्ता ने उसे घर में बंद कर दिया और घर से चला गया। लगभग आधे घंटे के बाद श्री पूर्णेन्दु बाबू-पीडब्लू 3, जो अपीलकर्ता और अभियोक्ता दोनों के सामान्य मित्र हैं, वहां आए और कमरे का ताला खोला, तब तक उसने पड़ोसियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए शोर नहीं मचाया। उपर्युक्त परिस्थिति स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि अभियोजन पक्ष का मामला स्वाभाविक और संभावित नहीं है। अभियोक्ता और पीडब्लू 3 में से किसी ने भी पुलिस को कथित अपराध के संबंध में सूचित नहीं किया है, जो अभियोक्ता द्वारा घर से ताला खोलने के बाद अपीलकर्ता द्वारा किया गया है। अभियोजन पक्ष द्वारा दिया गया कारण यह है कि पीडब्लू 3 अपीलकर्ता और अभियोक्ता के बीच विवाह का समझौता कराने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहा था। ऐसा नहीं हुआ और इसलिए, 25.2.93 को क्षेत्राधिकार वाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। उसके और अपीलकर्ता के बीच समझौते के बारे में पीडब्लू 1 का उपरोक्त कथन साबित नहीं हुआ

क्योंकि पीडब्लू 3 ने अपने साक्ष्य में कहा है कि उसे कथित अपराध के बारे में कुछ भी पता नहीं है।

9. इसके अलावा, क्षेत्राधिकार वाली पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करने में लगभग 11 दिनों की अत्यधिक देरी हुई है। अपीलकर्ता द्वारा कथित अपराध किए जाने के बाद उचित अवधि के भीतर शिकायत दर्ज न करने के लिए अभियोक्ता द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण यह है कि वह अपने घर गई और अपीलकर्ता द्वारा किए गए अपराध के बारे में अपनी मां को बताया और पूर्णेंद्र बाबू - पीडब्लू 3 के आश्वासन पर, मां दो-चार दिनों तक चुप रही, इस आश्वासन पर कि वह मामले में कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा, देरी के बारे में अभियोक्ता द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण यह है कि अपराध किए जाने के समय अपीलकर्ता ने उसे धमकी दी थी कि यदि उसने उसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कराई, तो उसे मार दिया जाएगा। उक्त स्पष्टीकरण एक बार फिर से मान्य स्पष्टीकरण नहीं है। इसके अलावा, उच्च न्यायालय द्वारा शिकायत तुरंत या उचित अवधि के भीतर दर्ज न करने के बारे में दिए गए कारण के बारे में, इसने देखा है कि बलात्कार के मामले में, पीड़ित लड़की कलंक के डर से पुलिस स्टेशन जाने और मामले को सबके सामने लाने की हिम्मत नहीं करती है, जो बलात्कार की शिकार लड़कियों के साथ जुड़ा होगा। साथ ही, ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए कारण जो अपीलकर्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करने में देरी के बारे में अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को सही ठहराते हैं, उच्च न्यायालय द्वारा आपत्तिजनक निर्णय में गलत तरीके से स्वीकार कर लिया गया है। इसके अलावा, देरी के बारे में उच्च न्यायालय द्वारा की गई आगे की टिप्पणी यह है कि अभियोक्ता के साथ-साथ उसकी माँ ने पीडब्लू 3, जो उन दोनों का एक सामान्य मित्र है और पीडब्लू 4, डॉक्टर जिसके साथ बलात्कार की शिकार लड़की नर्स के रूप में काम कर रही थी, के हस्तक्षेप से न्याय पाने की कोशिश की। जब ऐसा नहीं हुआ, तो 11 दिनों की अवधि बीत जाने के बाद, अपीलकर्ता द्वारा किए गए अपराध के लिए क्षेत्राधिकार वाले पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने यह कारण भी दर्ज किया है कि अभियोक्ता के पास घटना की तारीख 14.2.93 के बजाय अलग बताने का हर अवसर था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जो कारण कानून में मान्य नहीं है। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने विद्वान ट्रायल जज द्वारा की गई टिप्पणी को स्वीकार कर लिया जिसमें अभियोक्ता द्वारा अपने साक्ष्य में दिया गया स्पष्टीकरण कि पुलिस को मामले की सूचना देने की स्थिति में अपीलकर्ता द्वारा उसे जान से मारने का भय दिखाया गया था, कानून में पूरी तरह से मान्य नहीं है। यह न केवल अप्राकृतिक है बल्कि असंभव भी है। इसलिए अपीलकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में 11 दिनों की अत्यधिक देरी अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है। एफआईआर दर्ज करने में अत्यधिक देरी के बारे में यह महत्वपूर्ण पहलू न केवल अभियोजन पक्ष के मामले को स्वीकार करने योग्य नहीं बनाता है बल्कि ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा आरोपित निर्णयों में दिए गए कारण और टिप्पणियां कानून में पूरी तरह से मान्य नहीं हैं और उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए, असंतोषजनक कारण बताकर एफआईआर दर्ज करने में देरी को स्वीकार करने में निचली अदालतों द्वारा किए गए निष्कर्ष और टिप्पणियों को

इस न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि निष्कर्ष और कारण कानून की दृष्टि से गलत हैं।

10. आगे इस मामले में, पीडब्लू 3, जो अपीलकर्ता और अभियोक्ता का सामान्य मित्र है, अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह उस मामले के बारे में कुछ नहीं जानता जिसके लिए उसे मामले में गवाही देने के लिए अदालत से नोटिस मिला था। पीडब्लू 4 ने अपने साक्ष्य में कहा है कि अभियोक्ता उसकी परीक्षा की तिथि अर्थात् 16.11.95 को पिछले तीन वर्षों से उसके कक्ष में निजी तौर पर नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त कर रही थी। उसने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि 14.2.93 को जब उसने अपना कक्ष खोला तो अभियोक्ता उसके कक्ष में आई और आगे कहा कि उसकी माँ ने उसे कुछ नहीं बताया। अभियोजन पक्ष ने उसके साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया है, अभियोक्ता द्वारा उससे जिरह की गई, अपनी जिरह में उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने पुलिस को बताया है कि उसे घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि न तो अभियोक्ता और न ही उसकी माँ ने उन्हें घटना के बारे में बताया तथा आगे कहा कि उन्हें मामले के बारे में कुछ भी पता नहीं है।

11. इसके अलावा, अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करने के लिए न तो डॉक्टर और न ही 1.0. की ट्रायल कोर्ट के समक्ष जांच की गई है। अपीलकर्ता ने ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ उच्च न्यायालय के ध्यान में यह बात लाने में सही किया कि मामले में उपरोक्त दो महत्वपूर्ण गवाहों की जांच न किए जाने से अपीलकर्ता के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, क्योंकि अगर डॉक्टर की जांच की गई होती तो वह अभियोक्ता के निजी अंग या उसके शरीर के किसी अन्य भाग पर लगी किसी चोट और हाइमन परत आदि की प्रकृति के बारे में सबूत जुटा सकता था, ताकि अभियोजन पक्ष की कहानी की पुष्टि हो सके कि अपीलकर्ता द्वारा बलात्कार किए जाने के दौरान अभियोक्ता को असहनीय दर्द हुआ था। घटना के 12 दिनों के बाद उसकी जांच करने वाले डॉक्टर की जांच न किए जाने से बचाव पक्ष के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि अभियोक्ता की जांच अपीलकर्ता द्वारा कथित अपराध किए जाने के 12 दिनों के बाद की गई थी, क्योंकि उस समय तक बलात्कार के निशान गायब हो गए होंगे। अगर यह मान भी लिया जाए कि पीड़िता की योनिच्छद टूटी हुई थी और उसके गुप्तांग या शरीर के किसी अन्य भाग पर कोई चोट नहीं पाई गई थी, तो भी योनिच्छद के फटने के कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में अभियोक्ता एक कामकाजी लड़की थी और वह अपने घर की चारदीवारी के भीतर बेकार की जिंदगी नहीं जी रही थी। उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया उक्त तर्क कानून की दृष्टि से पूरी तरह गलत है।

12. पीडब्लू 3 और पीडब्लू 4 के साक्ष्य के उपरोक्त कथन के मद्देनजर, जिनका साक्ष्य अभियोजन पक्ष के लिए अपने मामले के अनुसार घटनाओं की श्रृंखला को साबित करने के लिए महत्वपूर्ण है, उपरोक्त गवाहों के साक्ष्य के बयान ने अभियोजन पक्ष के मामले को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। इसलिए, निचली अदालतें, किसी भी तरह से, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर यह नहीं मान सकती थीं कि अपीलकर्ता धारा 376, आईपीसी के तहत अपराध करने का दोषी है। इसके अलावा, अभियोक्ता के अनुसार, पीडब्लू 3 जिस पर अपराध के घटनास्थल से उसे बचाने का आरोप है, ने

अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि वह घटना के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, इसलिए वह अभियोजन पक्ष के संस्करण का समर्थन नहीं करता है। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के इस निष्कर्ष को गलत तरीके से स्वीकार कर लिया है कि अपीलकर्ता को डॉक्टर से पूछताछ न करने के कारण कोई पूर्वाग्रह नहीं है, क्योंकि वह पीडब्लू 4 के निजी अस्पताल में नर्स के रूप में काम कर रही थी और एक नर्स होने के नाते वह जानती थी कि बलात्कार किए जाने की सूचना गंभीर प्रकृति की है और अगर घटना सच होती तो वह पुलिस को सूचना देने में संकोच नहीं करती। इसके अलावा, निचली अदालतों का यह निष्कर्ष कि इस मामले में जांच करने वाले अभियोजन पक्ष द्वारा आई.ओ. से पूछताछ न करने से अपीलकर्ता के मामले में कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ है, क्योंकि अभियोजन पक्ष के गवाह अभियोजन पक्ष के प्रतिकूल थे, जिनकी या तो जांच की गई थी या अभियोजन पक्ष द्वारा उन्हें प्रतिकूल घोषित किया गया था, जो तर्क कानून में पूरी तरह से अस्थिर है। इसलिए, मामले में उपरोक्त दो गवाहों से पूछताछ न करने के संबंध में निचली अदालत और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष और कारणों ने अपीलकर्ता के मामले में कोई पूर्वाग्रह नहीं किया है, निचली अदालतों का पूरी तरह से गलत दृष्टिकोण है। इस कारण से भी, हमें यह मानना होगा कि आरोपित निर्णय में दर्ज निष्कर्ष और कारण कि ट्रायल कोर्ट का यह मानना उचित था कि अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप साबित कर दिया है और उसने अभियोक्ता पर अपराध किया है, पूरी तरह से गलत है और यह कानून में पूरी तरह से अस्थिर है।

13. निचली अदालत द्वारा दर्ज अपीलकर्ता की सजा के संबंध में निष्कर्ष जिसे उच्च न्यायालय ने अभियोक्ता की एकमात्र गवाही के आधार पर स्वीकार किया है, जो उसकी मां पीडब्लू 2 के साक्ष्य द्वारा समर्थित है, एक बार फिर उच्च न्यायालय की ओर से एक गलत दृष्टिकोण है। अपीलकर्ता द्वारा कथित बलात्कार का अपराध बिना किसी सबूत के स्थापित हो गया है क्योंकि अभियोजन पक्ष अभियोक्ता द्वारा बताई गई घटनाओं की श्रृंखला को साबित करने में विफल रहा है। चूंकि पीडब्लू 3 और पीडब्लू 4 के साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन दूसरी ओर, उनके साक्ष्य ने अभियोजन पक्ष की कहानी को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। इसलिए, निचली अदालतें अपीलकर्ता को आरोप का दोषी नहीं मान सकती थीं और उसे बलात्कार के अपराध के लिए दोषी ठहराकर सजा नहीं दे सकती थीं।

14. इसके अलावा, एक और मजबूत परिस्थिति जो आपके दिमाग में आई है, वह यह है कि वे एक-दूसरे से अच्छी तरह परिचित थे क्योंकि वे सहपाठी थे और वे एक-दूसरे से मिलते-जुलते थे। बचाव पक्ष के वकील ने वैकल्पिक रूप से तर्क दिया था कि अपीलकर्ता ने उसकी सहमति से यौन संबंध बनाए थे। उच्च न्यायालय ने उक्त तर्क को स्वीकार न करते हुए कारण बताए कि अपीलकर्ता यह स्पष्ट करने में विफल रहा कि किन परिस्थितियों में उसने अभियोक्ता की सहमति से यौन संबंध बनाए, जब वह उसके घर में बंद थी। अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि अभियोक्ता के साथ यह सहमति से यौन संबंध था, इस कारण से माना जाना चाहिए कि वह स्वयं अपीलकर्ता के घर गई थी, हालांकि उसका कथन यह है कि वह अपीलकर्ता के अनुरोध पर अपनी पुस्तक वापस लेने गई थी, जो उसने उसे दी थी। यह इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए

एक मजबूत परिस्थिति है कि अपीलकर्ता का बचाव मामला सहमति से यौन संबंध है। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अपीलकर्ता द्वारा अपराध किए जाने के बाद उसने कमरे को बाहर से बंद कर दिया था और चला गया था। आधे घंटे के बाद पुमेंदु बाबू-पीडब्लू 3 पहुंचे और कमरे का ताला खोला। इस कहानी पर यकीन करना असंभव है और अभियोक्ता ने घटना की तारीख से तुरंत या उचित अवधि के भीतर शिकायत दर्ज नहीं कराई है। अभियोक्ता द्वारा 11 दिन बीत जाने के बाद निर्विवाद रूप से शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस संबंध में, राजू बनाम मध्य प्रदेश राज्य में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करना उचित है, जिसका प्रासंगिक पैराग्राफ हमारे निष्कर्ष के समर्थन में बेहतर समझ के लिए नीचे उद्धृत किया गया है:

"12. गुरमीत सिंह मामले में 1983 में दंड संहिता की धारा 375 और 376 में संशोधन का संदर्भ दिया गया है, जिससे बलात्कार से संबंधित दंड प्रावधानों को और अधिक कठोर बनाया गया है, और साक्ष्य अधिनियम की धारा 114-ए का भी संदर्भ दिया गया है, जिसमें कथित बलात्कार के मामले में सहमति से यौन संबंध के आरोपों के संबंध में उठाए जाने वाले अनुमान के संबंध में बताया गया है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि धारा 113-ए और 113-बी भी उसी संशोधन द्वारा साक्ष्य अधिनियम में डाली गई थी, जिसके द्वारा आत्महत्या और दहेज हत्या के मामलों में अभियुक्तों के खिलाफ कुछ अनुमान लगाए गए हैं। इस प्रकार, ये दोनों धाराएँ अभियोजन पक्ष के पक्ष में स्पष्ट अनुमान लगाती हैं, लेकिन बलात्कार के संबंध में कोई समान अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि धारा 114-ए के तहत अनुमान अपनी प्रयोज्यता में अत्यधिक प्रतिबंधित है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जहाँ तक बलात्कार के आरोपों का सवाल है, अभियोक्ता के साक्ष्य की जाँच घायल व्यक्ति के साक्ष्य के रूप में की जानी चाहिए। गवाह जिसकी मौके पर मौजूदगी संभावित है, लेकिन यह कभी नहीं माना जा सकता कि उसके बयान को, बिना किसी अपवाद के, सत्य के रूप में लिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उसके बयान को, सबसे अच्छे रूप में, इस सिद्धांत पर आंका जा सकता है कि आम तौर पर कोई भी घायल गवाह झूठ नहीं बोलेगा या किसी व्यक्ति को गलत तरीके से फंसाएगा। हमारा मानना है कि इन सिद्धांतों के तहत ही इस मामले और इस तरह के अन्य मामलों की जांच की जानी चाहिए।"

15. उपर्युक्त कारणों से अभियोजन पक्ष का मामला स्वाभाविक, सुसंगत और विश्वास करने योग्य नहीं है कि अपीलकर्ता द्वारा कथित अपराध के लिए उसकी दोषसिद्धि और सजा कायम रखी जा सके।

16. ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ हाई कोर्ट को भी देरी के संबंध में रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों की सराहना करनी चाहिए थी और अभियोजन पक्ष द्वारा एफआईआर दर्ज करने में 11 दिनों की देरी और शिकायतकर्ता गवाहों, यानी डॉक्टर और 1.0 से पूछताछ न करने के बारे में उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया जाना चाहिए था। जिससे न केवल अपीलकर्ता के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, बल्कि अभियोजन पक्ष के मामले ने भी इस न्यायालय के मन में उचित संदेह पैदा किया है। इसलिए, संदेह का लाभ अपीलकर्ता को मिलना चाहिए। जैसा कि हमने ऊपर कहा है कि अभियोजन पक्ष की गवाही सबसे

अस्वाभाविक और विश्वास करने के लिए असंभव है और इसलिए यह दोषसिद्धि और सजा को बनाए रखने के लिए इसे स्वीकार करने के लिए विश्वास को प्रेरित नहीं करती है। इसलिए, हमारा विचार है कि इस न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए विवादित निर्णय में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। तदनुसार, हम अपील को स्वीकार करते हैं और विवादित निर्णय को रद्द करते हैं।

17. यदि अपीलकर्ता ने जमानत बांड निष्पादित कर दिया है, तो उसे मुक्त किया जा सकता है।

आर.पी.

अपील स्वीकृत।

नागेन्द्रप्पा नाटिकर

बनाम

नीलम्मा

(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 11800/2013)

15 मार्च, 2013

[के.एस. राधाकृष्णन और दीपक मिश्रा, जे.जे.]

हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956:

धारा 18 - पत्नी द्वारा भरण-पोषण का दावा करने वाला वाद - निर्णय: पक्षकारों के बीच समझौता होने के बावजूद, आदेश 23, नियम 3 सीपीसी और धारा 125 सीआरपीसी के तहत स्थायी गुजारा भत्ता देने के आदेश के आधार पर यह मामला बनाए रखने योग्य है - दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 125 - सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - आदेश 23, नियम 23 - अनुबंध अधिनियम, 1872 - धारा 25..

पति द्वारा दायर की गई इस याचिका में न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या पति और पत्नी द्वारा धारा 23, नियम 3 सीपीसी के तहत किया गया समझौता, जिसमें स्थायी गुजारा भत्ते के लिए एक समेकित राशि पर सहमति व्यक्त की गई थी, जिससे भविष्य में भरण-पोषण के लिए किसी भी दावे को छोड़ दिया गया था, जिसे सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कार्यवाही में न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, क्या यह पत्नी को हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 18 के तहत दायर मुकदमे में भरण-पोषण का दावा करने से रोकेगा।

याचिका को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा: 1.1 धारा 125 सीआरपीसी के तहत समझौता या अन्यथा पारित कोई भी आदेश हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 18(2) के तहत पत्नी को उपलब्ध उपचार को समाप्त नहीं कर सकता। धारा 125 सीआरपीसी एक सामाजिक कानून है जो उस पत्नी को भरण-पोषण के रूप में संक्षिप्त और त्वरित राहत प्रदान करता है जो अपना और अपने बच्चों का भरण-पोषण करने में असमर्थ है। धारा 125 का उद्देश्य पक्षों की स्थिति और व्यक्तिगत अधिकारों का पूर्ण और अंतिम निर्धारण प्रदान करना नहीं है, जो कि एक सिविल कार्यवाही की प्रकृति का है; और धारा 125 सीआरपीसी के तहत पारित आदेश

अस्थायी है और सिविल न्यायालय में अधिकारों के अंतिम निर्धारण के अधीन है। [पैरा 10-11) [431-बी-डी-ई]

1.2 अनुबंध अधिनियम की धारा 25 में प्रावधान है कि कोई भी समझौता जो सार्वजनिक नीति के विपरीत है, वह कानून की अदालत में लागू नहीं हो सकता है और ऐसा समझौता शून्य है, क्योंकि इसका उद्देश्य गैरकानूनी है। [पैरा 11) [431-डी-ई]

1.3 पारिवारिक न्यायालय और उच्च न्यायालय ने सही माना है कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 18 के तहत मुकदमा पूरी तरह से स्वीकार्य है, भले ही आदेश 23 के तहत पक्षों के बीच समझौता हो गया हो। नियम 3 सी.पी.सी. [पैरा 9) [431-ए-बी]

सिविल अपील की क्षेत्राधिकार: एसएलपी (सिविल) संख्या 11800/2013।

कर्नाटक उच्च न्यायालय, गुलबर्गा सर्किट बेंच के एमएफए संख्या 31979/2010 के दिनांक 28.03.2011 के निर्णय एवं आदेश से।

याचिकाकर्ता की ओर से राजा वेंकटप्पा नाइक, राजा राघवेंद्र नाइक, एस.के. टंडन, आर.के. गुप्ता, रामेश्वर प्रसाद गोयल।

न्यायालय का निर्णय

न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन द्वारा सुनाया गया। 1. विलम्ब क्षमा किया गया।

2. इस मामले में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या पति-पत्नी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश XX.III नियम 3 के तहत किया गया समझौता, स्थायी गुजारा भत्ता के लिए एक समेकित राशि पर सहमति जताते हुए, जिससे भविष्य में भरण-पोषण के लिए किसी भी दावे को छोड़ दिया जाता है, जिसे दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत कार्यवाही में न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 18 के तहत दायर मुकदमे में पत्नी को भरण-पोषण का दावा करने से रोकेगा।

3. याचिकाकर्ता (पति) और प्रतिवादी (पत्नी) के बीच विवाह 24.5.1987 को हुआ था। यह आरोप लगाते हुए कि याचिकाकर्ता अपनी पत्नी का भरण-पोषण नहीं कर रहा है, प्रतिवादी ने गुलबर्गा में प्रथम अतिरिक्त जेएमएफसी के समक्ष भरण-पोषण के लिए धारा 125 सीआरपीसी के तहत एक आवेदन दायर किया, जो विविध मामला संख्या 234/1992 था। जब मामला लंबित था, तब पार्टियों द्वारा 3.9.1994 को आदेश XX III नियम 3 सीपीसी के तहत एक आवेदन पेश किया गया था जिसमें कहा गया था कि पक्ष एक समझौते पर पहुंच गए हैं, जिसके द्वारा प्रतिवादी स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में 8,000/- रुपये की राशि प्राप्त करने के लिए सहमत हो गई थी और वह भविष्य में भरण-पोषण या भरण-पोषण में वृद्धि के लिए कोई दावा नहीं करेगी। सहमति पत्र दिनांक 30.3.1990, जो कन्नड़ में है, उसका अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार है:

"सहमति पत्र:

मैं, नीलम्मा पत्नी नागेंद्र नटिकर, उम्र 23 वर्ष, निवासी पुराना शाहाबाद, अपने पति नागेंद्र नटिकर के पक्ष में बिना किसी दबाव और गलत बयानी के स्वतंत्र इच्छा और सहमति से यह सहमति पत्र निष्पादित करती हूँ।

नागेंद्र नटिकर के साथ मेरी शादी के बाद, मैं अपने खराब स्वास्थ्य के कारण अपने पति के साथ वैवाहिक जीवन को खुशहाल तरीके से नहीं जी सकी क्योंकि मेरी शादी से पहले मैं पीठ दर्द, बाएं हाथ और बाएं पैर में लकवा के दौरे से पीड़ित थी और मिर्गी (फिट्स रोग) से भी पीड़ित थी और इसलिए मैंने खुद ही वैवाहिक जीवन से हटने का फैसला किया है। मैंने आपसी सहमति से तलाक के लिए अपनी सहमति दे दी है। अगर मेरे पति किसी और के साथ दूसरी शादी करते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

मेरी शादी से पहले मैं एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। मैंने अपने पिता से कहा था कि वे मेरी शादी किसी और के साथ न मनाएँ। मेरे पिता ने जबरन नागेंद्रप्पा नटिकर से शादी करवा दी। अब से मैं कोई और दावा नहीं करूँगी और भविष्य में अपने अधिकारों को भी खो दूँगी और मैं मुआवज़ा, भरण-पोषण या गुजारा भत्ता का दावा नहीं करूँगी। मैं 8000/- रुपये के भुगतान से संतुष्ट हूँ और मैं अपने पति के खिलाफ कोई और दावा नहीं करूँगी।

मैंने अपने पति के पक्ष में बिना किसी दबाव के और बिना किसी गलत बयानी या दबाव के इस सहमति पत्र को निष्पादित किया है। मेरे पिता-माता या किसी अन्य परिवार के सदस्य को इस सहमति पत्र को निष्पादित करने में कोई आपत्ति नहीं है।

निष्पादक के हस्ताक्षर

नीलम्मा

(कन्नड़ में हस्ताक्षरित)

गवाहों के हस्ताक्षर:

1. तिप्पन्ना (कन्नड़ में हस्ताक्षरित)
2. देविन्द्रप्पा (कन्नड़ में हस्ताक्षरित)
3. सैयद जबीउल्लाह साहब (लेखक द्वारा हस्ताक्षरित) "

न्यायालय ने उसी दिन निम्नलिखित आदेश पारित किया:

"दोनों पक्ष उपस्थित हैं। दोनों पक्ष और अधिवक्ता समझौता याचिका दायर करते हैं। समझौता याचिका की विषय-वस्तु उन्हें पढ़कर सुनाई जाती है और समझाई जाती है। वे न्यायालय के समक्ष इसके निष्पादन को स्वीकार करते हैं। प्रतिवादी ने समझौते के अनुसार भरण-पोषण की पूर्ण संतुष्टि के लिए न्यायालय के समक्ष 8000/- (आठ हजार) रुपए का भुगतान किया। समझौते के मद्देनजर याचिका खारिज कर दी गई।"

4. इसके बाद प्रतिवादी पत्नी ने धारा 127 सीआरपीसी के तहत गुलबर्गा के पारिवारिक न्यायालय में एक विविध आवेदन संख्या 34/2003 दायर किया, जिसमें पहले के आदेश को रद्द करने और भविष्य में भरण-पोषण देने का अनुरोध किया गया, जिसका याचिकाकर्ता ने यह कहते हुए विरोध किया कि 3.9.1994 को भरण-पोषण के दावे के संबंध में पक्ष पहले ही समझौता कर चुके थे और इसलिए पहले के आदेश को रद्द करने का आवेदन स्वीकार्य नहीं है। न्यायालय ने पति की दलील को स्वीकार कर लिया और यह

विचार किया कि चूंकि ऐसा आदेश अभी भी लागू है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इसे रद्द नहीं किया गया है, इसलिए धारा 127 सीआरपीसी के तहत आवेदन पर विचार करना संभव नहीं होगा। इसलिए, आवेदन को 31.7.2006 को खारिज कर दिया गया।

5. हमने देखा कि जब धारा 127 सीआरपीसी के तहत आवेदन लंबित था, प्रतिवादी पत्नी ने धारा 18 के तहत पारिवारिक न्यायालय, गुलबर्गा के समक्ष ओ.एस. संख्या 10/2005 दायर किया, जिसमें 2,000/- रुपये प्रति माह की दर से भरण-पोषण का दावा किया गया। याचिकाकर्ता पति ने इस दावे का विरोध किया और तर्क दिया कि धारा 125 सीआरपीसी के तहत दायर विविध मामला संख्या 234/1992 में पक्षों के बीच हुए समझौते के मद्देनजर, प्रतिवादी किसी भी मासिक भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकता और इसलिए अधिनियम की धारा 18 के तहत दायर मुकदमा स्वीकार्य नहीं था। स्वीकार्यता का प्रश्न एक प्रारंभिक मुद्दे के रूप में उठाया गया था। पारिवारिक न्यायालय ने अपने दिनांक 15.9.2009 के आदेश द्वारा माना कि धारा 125 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही में पक्षों के बीच किया गया समझौता अधिनियम की धारा 18 के तहत मुकदमा स्वीकार करने में बाधा नहीं होगा।

6. इसके बाद 30.9.2010 को अंतिम रूप से मुकदमे की सुनवाई हुई और पारिवारिक न्यायालय ने यह कहते हुए मुकदमे का फैसला सुनाया कि प्रतिवादी मुकदमा दायर करने की तिथि से प्रतिवादी पति से 2,000 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता पाने का हकदार है।

7. उक्त आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने एम.एफ.ए. संख्या 31979/2010 के तहत अपील दायर करके मामले को उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया, जिसे उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 28.3.2011 के निर्णय द्वारा खारिज कर दिया, जिसके विरुद्ध यह विशेष अनुमति याचिका प्रस्तुत की गई है।

8. याचिकाकर्ता पति की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजा वेंकटप्पा नाइक ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 18 के तहत दायर मुकदमा दिनांक 3.9.1994 के आदेश के मद्देनजर पोषणीय नहीं है, जिसमें सहमति शर्तों को स्वीकार किया गया है और धारा 125 सीआरपीसी के तहत गुजारा भत्ता के लिए एक समेकित राशि का आदेश दिया गया है।

9. हम पारिवारिक न्यायालय के तर्क से पूरी तरह सहमत हैं और उच्च न्यायालय ने भी पुष्टि की है कि अधिनियम की धारा 18 के तहत मुकदमा पूरी तरह से स्वीकार्य है, भले ही पक्षकारों के बीच सी.पी.सी. के आदेश x x II नियम 3 के तहत समझौता हो गया हो और न्यायालय ने अपने दिनांक 3.9.1994 के आदेश में इसे स्वीकार कर लिया हो।

10. धारा 125 सी.आर.पी.सी. एक सामाजिक कानून है जो उस पत्नी को भरण-पोषण के रूप में संक्षिप्त और त्वरित राहत प्रदान करता है जो अपना और अपने बच्चों का भरण-पोषण करने में असमर्थ है। धारा 125 का उद्देश्य पक्षकारों की स्थिति और व्यक्तिगत अधिकारों का पूर्ण और अंतिम निर्धारण प्रदान करना नहीं है, जो कि एक सिविल कार्यवाही की प्रकृति का है, हालांकि यह सी.आर.पी.सी. के प्रावधानों द्वारा

शासित है और धारा 125 सी.आर.पी.सी. के तहत दिया गया आदेश अस्थायी है और सिविल न्यायालय में अधिकारों के अंतिम निर्धारण के अधीन है।

11. संविदा अधिनियम की धारा 25 में प्रावधान है कि कोई भी समझौता जो सार्वजनिक नीति के विरुद्ध है, वह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है तथा ऐसा समझौता शून्य है, क्योंकि इसका उद्देश्य गैरकानूनी है। धारा 125 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही प्रकृति में संक्षिप्त है तथा इसका उद्देश्य पत्नी को शीघ्र उपचार प्रदान करना है तथा धारा 125 सीआरपीसी के तहत समझौता या अन्यथा पारित कोई भी आदेश अधिनियम की धारा 18(2) के तहत पत्नी को उपलब्ध उपचार को समाप्त नहीं कर सकता।

12. उपर्युक्त कानूनी स्थिति होने के कारण, हमें पारिवारिक न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण में कोई त्रुटि नहीं दिखती, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय ने की है। इसलिए, याचिका को समय रहते खारिज किया जाता है।

आर.पी.

एसएलपी खारिज।

शांतिलाल गुलाबचंद मुथा

बनाम

टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड और अन्य

(सिविल अपील संख्या 6162/2005)

18 मार्च, 2013.

[डॉ. बी.एस. चौहान और फकीर मोहम्मद

इब्राहिम कलीफुल्ला, न्यायाधीश]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908:.

आदेश 8, नियम 10 - प्रतिवादी द्वारा लिखित बयान दाखिल करने में विफलता पर निर्णय - माना गया: 0. 8, नियम 10 के तहत राहत विवेकाधीन है, और अदालत को ऐसी शक्ति का प्रयोग करते समय अधिक सतर्क रहना होगा, जहां प्रतिवादी लिखित बयान दाखिल करने में विफल रहता है - अदालत को यह संतुष्ट होना चाहिए कि प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किए जाने के बावजूद ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिसे साबित करने की आवश्यकता है, और अदालत को ऐसा निर्णय पारित करने के लिए कारण बताने चाहिए - वर्तमान मामले में, ट्रायल कोर्ट ने इस बात की जांच नहीं की है कि क्या वाद सीमा के भीतर दायर किया गया था और क्या दलीलों के आधार पर, उसके द्वारा दी गई राहत दी जा सकती थी - अदालत ने डिक्री पारित करने से पहले मामले की प्रथम दृष्टया जांच करना भी उचित नहीं समझा - चूंकि ट्रायल कोर्ट आदेश 8 नियम 10 के तहत आगे बढ़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मापदंडों को पूरा करने में विफल रहा, इसलिए उसके द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को अलग रखा गया और मामले को नए सिरे से तय करने के लिए वापस भेज दिया गया - अपीलकर्ता प्रदान की गई अवधि के भीतर लिखित बयान दाखिल करने के लिए स्वतंत्र है।

बा/राज तनेजा एवं अन्य। वी. सुनील मदान और अन्य। 1999 (2) सप्ल. एससीआर 258 = एआईआर 1999 एससी 3381; बोगीधोला टी एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड और अन्य। वी. हीरा लाल सोमानी, 2007 (12) एससीआर 1153 = एआईआर 2008 एससी 911; रमेश चंद अरदावतल्या बनाम अनिल पंजवानी 2003 (3) एससीआर 1149 = एआईआर 2003 एससी 2508 • विश्वसनीय पर।

केस लॉ संदर्भ:

1999 (2) अनुपूरक एस.सी.आर. 258	पैरा 3 पर निर्भर करता है
2007 (12) एस.सी.आर. 1153	पैरा 5 पर निर्भर करता है
2003 (3) एस.सी.आर. 1149	पैरा 5 पर निर्भर करता है

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 6162/2005.

वाद संख्या 1924/1998 में नोटिस ऑफ मोशन संख्या 503/2004 में अपील संख्या 478/2005 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के दिनांक 22.06.2005 के निर्णय एवं आदेश से।

प्रसेनजीत केसवानी, पवन कुमार बंसल (वी.डी. खन्ना के लिए) अपीलकर्ता के लिए।

देवमात्या बनर्जी (माणिक करंजावाला के लिए) प्रतिवादियों के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश सुनाया गया

आदेश

1. यह अपील बॉम्बे उच्च न्यायालय के दिनांक 22.6.2005 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जो वाद संख्या 1924/1988 में नोटिस ऑफ मोशन संख्या 503/2004 में अपील संख्या 478/2005 में पारित किया गया था।

2. इस अपील को जन्म देने वाले तथ्य और परिस्थितियां हैं:

ए. अपीलकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 1 से 9,58,913/- रुपए की राशि में पांच टाटा डीजल वाहन खरीदे थे, जिसका भुगतान प्रतिवादी संख्या 2 के माध्यम से 8 किस्तों में पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार किया जाना था। अपीलकर्ता का आरोप है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 - अपीलकर्ता के बैंकर के नाम पर आठ विनिमय पत्र तैयार किए गए थे, जिनके माध्यम से पूरी राशि का भुगतान किया गया था। प्रतिवादी संख्या 1 ने 2.6.1988 को अपीलकर्ता और बैंकर के खिलाफ ब्याज सहित 5,66,000/- रुपए की राशि की वसूली के लिए वाद संख्या 1924/1988 दायर किया। अपीलकर्ता को समन भेजा गया और वह मुकदमा लड़ने के लिए वकील के माध्यम से उपस्थित हुआ।

हालांकि, बाद में यह मानकर कि पूरी राशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, उसने लिखित बयान दाखिल नहीं किया। उच्च न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (जिसे आगे 'सीपीसी' कहा जाएगा) के आदेश v IIII नियम 10 के प्रावधानों के

तहत दिनांक 12.11.2003 के निर्णय और डिक्री द्वारा वाद में शामिल किसी भी मुद्दे पर विचार किए बिना या वाद में की गई दलीलों पर ध्यान दिए बिना ही वाद को जारी कर दिया।

ख. व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने दिनांक 12.11.2003 के एकपक्षीय निर्णय को रद्द करने के लिए उक्त मुकदमे में प्रस्ताव संख्या 503/2004 की सूचना प्रस्तुत की, तथापि, इसे दिनांक 10.12.2004 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि बॉम्बे उच्च न्यायालय के खंडपीठ के निर्णय के मद्देनजर इसे बनाए रखने योग्य नहीं माना गया, जिसमें यह माना गया था कि आदेश v III नियम 10 सीपीसी के तहत पारित किसी भी निर्णय को आदेश IX नियम 13 सीपीसी के तहत आवेदन के अधीन नहीं किया जा सकता है।

सी. व्यथित होकर अपीलकर्ता ने अपील दायर की जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ सहमति जताते हुए दिनांक 22.6.2005 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।

अतः यह अपील।

3. हमने अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री प्रसेनजीत केसवानी और प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान वकील श्री देबमालया बनर्जी को सुना है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

4. इस न्यायालय ने बा/राज तनेजा एवं अन्य बनाम सुनील मदान एवं अन्य, एआईआर 1999 एससी 3381 में इस मुद्दे पर विचार किया और माना कि ऐसी तथ्य-स्थिति में भी, न्यायालय को केवल इसलिए शिकायत में किए गए कथनों पर आँख मूंदकर कार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रतिवादी द्वारा लिखित कथन दायर नहीं किया गया है, जो वादी द्वारा उसमें बताए गए तथ्यों से अलग है। जहाँ प्रतिवादी द्वारा लिखित कथन दायर नहीं किया गया है, न्यायालय को आदेश v III, नियम 10, सीपीसी के तहत कार्यवाही करने में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। प्रतिवादी के खिलाफ निर्णय पारित करने से पहले उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भले ही शिकायत में बताए गए तथ्यों को स्वीकार कर लिया गया हो, फिर भी शिकायत में उल्लिखित किसी भी तथ्य को साबित करने की आवश्यकता के बिना वादी के पक्ष में निर्णय पारित किया जा सकता है। यह न्यायालय की संतुष्टि का मामला है और इसलिए, केवल इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिसे स्वीकार किए जाने के कारण साबित करने की आवश्यकता है, न्यायालय प्रतिवादी के खिलाफ सुविधाजनक रूप से निर्णय पारित कर सकता है जो लिखित कथन दायर करने में विफल रहा। हालांकि, अगर शिकायत में ही यह संकेत मिलता है कि मामले में तथ्य के विवादित प्रश्न शामिल हैं, जिसके बारे में शिकायत में ही दो अलग-अलग संस्करण दिए गए हैं, तो अदालत के लिए तथ्यात्मक विवाद को निपटाने के लिए वादी से तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता के बिना निर्णय पारित करना सुरक्षित नहीं होगा। आदेश v III, नियम 10 सीपीसी के तहत आगे बढ़ने की अदालत की शक्ति विवेकाधीन है। अदालत ने आगे कहा कि धारा 2(9) सीपीसी में परिभाषित निर्णय का अर्थ है न्यायाधीश द्वारा डिक्री या आदेश के लिए आधारों का दिया गया कथन। इसलिए, निर्णय में एक ऐसा दस्तावेज होना चाहिए जिससे यह पता चले कि मामले के तथ्य क्या थे और वह विवाद क्या था जिसे अदालत ने और किस तरीके से निपटाने की कोशिश की।

जिस तर्क की प्रक्रिया से अदालत अंतिम निष्कर्ष पर पहुंची और मुकदमे का फैसला सुनाया, वह निर्णय में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होना चाहिए। अदालत ने आगे कहा:-

"चाहे वह ऐसा मामला हो जिसमें प्रतिवादियों द्वारा लिखित बयान दाखिल करके विरोध किया जाता है, या ऐसा मामला हो जो एकपक्षीय रूप से आगे बढ़ता है और अंततः एकपक्षीय मामले के रूप में तय किया जाता है, या ऐसा मामला हो जिसमें लिखित बयान दाखिल नहीं किया जाता है और मामले का फैसला आदेश 8 नियम 10 के तहत किया जाता है, अदालत को एक निर्णय लिखना होता है जो संहिता के प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए या कम से कम उस तर्क को निर्धारित करना चाहिए जिसके द्वारा विवाद को हल किया जाता है।" (जोर दिया गया)

5. बोगीधोला टी एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम हीरा लाल सोमानी, एआईआर 2008 एससी 911 में, इस न्यायालय ने इसी तरह के विचार को दोहराते हुए कहा कि आदेश v III, नियम 10 सीपीसी के तहत डिक्री तब तक पारित नहीं की जानी चाहिए जब तक कि वाद में किए गए कथनों की पुष्टि न हो जाए। किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, न्यायालय को सीमा के मुद्दे पर भी निर्णय लेना चाहिए, यदि ऐसा है, तो।

(यह भी देखें: रमेश चंद अर्दवतल्या बनाम अनिल पंजवानी, एआईआर 2003 एससी 2508)

6. उपरोक्त के मद्देनजर, यह एक स्थापित कानूनी प्रस्ताव प्रतीत होता है कि आदेश v III नियम 10 सीपीसी के तहत राहत विवेकाधीन है, और अदालत को ऐसी शक्ति का प्रयोग करते समय अधिक सतर्क रहना चाहिए, जहां प्रतिवादी लिखित बयान दाखिल करने में विफल रहता है। ऐसी परिस्थितियों में भी, अदालत को यह संतुष्ट होना चाहिए कि प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किए जाने के बावजूद ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिसे साबित करने की आवश्यकता है, और अदालत को ऐसे निर्णय को पारित करने के लिए कारण बताने चाहिए, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, लेकिन निर्णय को पढ़कर, एक पक्ष को यह समझना चाहिए कि वे कौन से तथ्य और परिस्थितियाँ थीं जिनके आधार पर अदालत को आगे बढ़ना चाहिए, और किस तर्क के तहत मुकदमा सुनाया गया है।

7. इस मामले की जांच उपर्युक्त स्थापित कानूनी प्रस्तावों के आलोक में की जानी चाहिए। शिकायत से यह स्पष्ट है कि आठ विनिमय पत्र, सभी दिनांक 4.6.1982 के थे, जिनमें ब्याज सहित संबंधित राशि थी और प्रत्येक बिल को अपीलकर्ता द्वारा मर्केटाइल बैंक लिमिटेड, बॉम्बे में देय स्वीकार किया गया था और उक्त बिलों को प्रतिवादी/वादी द्वारा अपने बैंकों के साथ भुनाया गया था। शिकायत में यह भी स्वीकार किया गया है कि अपीलकर्ता के बैंक ने प्रतिवादी/वादी को संबंधित तिथियों पर उक्त राशि का भुगतान किया था, जैसा कि शिकायत के पैरा 5 में पांच राशियों का उल्लेख किया गया है। हालाँकि, चूंकि इससे पूरी मांग पूरी नहीं हुई, इसलिए निम्नलिखित प्रार्थना के साथ मुकदमा दायर किया गया:-

"प्रतिवादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 2 को आदेश दिया जाता है और फैसला सुनाया जाता है कि वे वादी को ऊपर पैराग्राफ 7 में उल्लिखित 999388.30

रुपये की राशि का भुगतान करें, साथ ही 5,66,000 रुपये की राशि पर मुकदमे की तारीख से भुगतान तक 18.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी दें।"

8. ट्रायल कोर्ट ने वाद संख्या 1924/1988 पर निर्णय देते हुए वाद पर दिनांक 12.11.2003 के निर्णय एवं डिक्री द्वारा निर्णय दिया, जो इस प्रकार है:-

"वादीगण के वकील उपस्थित हैं। प्रतिवादियों की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। लिखित बयान के अभाव में प्रतिवादियों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए मामला विचाराधीन है। वाद 1988 का है। अभी तक कोई लिखित बयान दाखिल नहीं हुआ है। इसलिए, वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादियों के विरुद्ध सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश v III नियम 10 के अंतर्गत 9,99,388.30 रुपये की राशि पर वाद की तिथि से वसूली तक 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज तथा लागत सहित डिक्री पारित की जाएगी। उपरोक्त शर्तों के अनुसार वादपत्र की केवल प्रार्थना (क) मंजूर की जाती है। तदनुसार डिक्री तैयार की जाए।"

9. अपीलकर्ता ने उक्त निर्णय और डिक्री को रद्द करने के लिए नोटिस ऑफ मोशन लिया जिसे खारिज कर दिया गया था और उक्त खारिज करने के आदेश को खंडपीठ ने मंजूरी दे दी है। हम इस मुद्दे की जांच नहीं कर रहे हैं कि क्या इस तरह के निर्णय और डिक्री को सीपीसी के आदेश IX नियम 13 के प्रावधानों के अधीन किया जा सकता है, लेकिन अदालत ने इस बात की जांच नहीं की है कि क्या मुकदमा सीमा के भीतर दायर किया गया था और क्या दलीलों के आधार पर अदालत द्वारा दी गई राहत दी जा सकती थी। अदालत ने डिक्री पारित करने से पहले मामले की प्रथम दृष्टया जांच करना भी उचित नहीं समझा, जैसा कि उपरोक्त उद्धरण से स्पष्ट है। यह पूरा विवादित निर्णय है।

10. चूंकि ट्रायल कोर्ट सीपीसी के आदेश v III नियम 10 के तहत आगे बढ़ने के लिए इस अदालत द्वारा निर्धारित मापदंडों को पूरा करने में विफल रहा, इसलिए ट्रायल कोर्ट के दिनांक 12.11.2003 के फैसले और डिक्री को रद्द किया जाता है और मामले को नए सिरे से तय करने के लिए ट्रायल कोर्ट को वापस भेजा जाता है। अपीलकर्ता आज से 3 सप्ताह की अवधि के भीतर लिखित बयान दाखिल करने के लिए स्वतंत्र है और ट्रायल कोर्ट उसके बाद कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र है। चूंकि मामला बहुत पुराना है, इसलिए हम ट्रायल कोर्ट से अनुरोध करते हैं कि वह मुकदमे को जल्द से जल्द समाप्त करे। मूल रिकॉर्ड, यदि कोई हो, तुरंत वापस भेजा जाए।

मामले से अलग होने से पहले, हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि हमने इस मुद्दे पर फैसला नहीं किया है कि क्या ऐसे मामले में सीपीसी के आदेश IX नियम 13 के तहत आवेदन बनाए रखने योग्य है।

11. तदनुसार अपील का निपटारा किया जाता है।

आर.पी.

अपील का निपटारा किया जाता है।

यह अनुवाद अधिवक्ता ज्ञान रंजन, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।